

NAME OF THE PUBLICATION	THE INDIAN EXPRESS
PAGE NO.	19
DATE	27-8-2021
LANGUAGE OF THE PUBLICATION	ENGLISH
PLACE OF PUBLICATION	CHANDIGARH

To register unorganised workers, govt launches e-SHRAM

ENSECONOMIC BUREAU

NEW DELHI, AUGUST 26

MINISTER OF Labour and Employment Bhupender Yadav on Thursday launched the e-SHRAM portal and handed it over to the states/UTs for registration of unorganised workers across the country. The government aims to register 38 crore unorganised workers such as construction labourers, migrant workforce, street vendors, and domestic workers, among others.

"For the first time in the history of India, a system is being made to register 38 crore unorganised workers. It will not only register them but would also be helpful in delivering various social security schemes being implemented by the Central and state governments," Yadav said.

The workers will be issued an e-SHRAM card containing a 12 digit unique number, which going ahead will help in inclusion of these workers in social security schemes, officials said. "More than 38 crore unorganised workers in the country will be registered under one portal and the registration under e-SHRAM is totally free and workers do not have to pay anything for his or her registration at Common Service Centres (CSCs) or anywhere," Labour Secretary Apurva Chandra said.

"... upon registration, workers shall be issued an e-SHRAM card with a unique universal account number and will be able to access the benefits of the various social security schemes through this card anywhere anytime," he said.

The government had earlier missed deadlines for creating the database, inviting criticism from the Supreme Court. A worker can register on the portal using his/her Aadhaar card number and bank account details, apart from filling other necessary details like date of birth, home town, mobile number, and social category. Detailed guidelines for operationalisation of the portal and mobilisation of workers have already been issued to the states/Union Territories, the

Government of India
Chandigarh

NAME OF THE PUBLICATION	DANIK JAGRAN
PAGE NO.	
DATE	27 8 2021
LANGUAGE OF THE PUBLICATION	HINDI
PLACE OF PUBLICATION	CHANDIGARH

38 करोड़ असंगठित श्रमिकों को मिलेगी सामाजिक सुरक्षा

जाब्यु नई दिल्ली: 38 करोड़ असंगठित और प्रवासी श्रमिकों का डाटाबेस तैयार करने और उन्हें सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने को केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुवार को ई-श्रम पोर्टल लांच किया। इसके लिए श्रमिकों को आधार नंबर, मोबाइल नंबर और बैंक खाता नंबर देना होगा। पंजीयन पूरी तरह से मुफ्त होगा और श्रमिक कामन सर्विस सेंटर पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। पंजीयन कराने वालों को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जारी किया जाएगा। फिलहाल पंजीयन कराने वाले श्रमिकों को दो लाख रुपये का दुर्घटना बीमा लाभ दिया जाएगा। घर में काम करने वालों से लेकर 10 से कम कर्मचारी वाली संस्था से जुड़े श्रमिक भी पोर्टल पर पंजीयन करा सकेंगे। एक मोबाइल नंबर से चार श्रमिकों का पंजीयन हो सकेगा। पंजीकृत होने वाले श्रमिकों के पास हर साल मैसेज आएगा और उसे यस करने पर पंजीयन अपडेट होता रहेगा। टोल फ्री काल सेंटर

डाटा बेस तैयार करने के लिए लांच किया गया ई-श्रम पोर्टल, मोबाइल और आधार नंबर से मुफ्त में होगा पंजीयन

भी गुरुवार से शुरू कर दिया गया। पोर्टल को विकसित करने से लेकर उससे जुड़े विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए केंद्र सरकार ने पांच साल के लिए 704 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अभी 400 से अधिक प्रकार के कार्यों को असंगठित क्षेत्रों में रखा गया है। राज्यों को श्रमिकों का पंजीयन इस पोर्टल पर करने के लिए कहा गया है। पंजीकृत श्रमिकों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा। पंजीयन के काम की लगातार निगरानी भी की जाएगी और इस काम के लिए राज्य स्तर पर वहां के मुख्य सचिव के नेतृत्व में निगरानी समिति बनाई जाएगी।